

न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बड़जलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 सभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या: 32/2024/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक 2.03.2024

अन्तर्गत धारा: 76 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. महादेव पुत्र श्री छीतरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम आमली तहसील एवं जिला बून्दी
.....अपीलांट

बनाम



1. श्रीमति कमलेश पत्नि सुरेश जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
2. अभिषेक पुत्र श्री सुरेश जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
3. रवि पुत्र श्री सुरेश जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
4. प्रीति अवयस्क पुत्री सुरेश जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी द्वारा प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमति कमलेश पत्नि सुरेश निवासी जवाहर नगर बून्दी
5. कांति बाई पुत्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल पत्नि कालू जी निवासी इन्द्रपुरिया तहसील के. पाटन जिला बून्दी
6. मंगली बेवा गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
7. शंकरलाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल निवासी जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
8. द्वारका पुत्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी
9. गोपाली पुत्री श्री छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल ग्राम उलेड़ा तहसील एवं जिला बून्दी
10. गोबरीलाल पुत्र श्री गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम आमली हाल जवाहर नगर बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी

....रेस्पो0

उपस्थित : श्री संजय पाटोदी, अभिभाषक –अपीलांट
श्री जितेन्द्र कोठारी, अभिभाषक – रेस्पो0

मि. अ. अ. 13/3/2025
अति. स. आयुक्त
कोटा

::निर्णयः:

दिनांक 17.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या 04/अपील/2023 बउनवान महोदव बनाम कमलेश वगै० में पारित निर्णय दिनांक 12.02.2024 के विरुद्ध अपील राज० भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांत के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर तहसीलदार, बून्दी द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 459 दिनांक 27.05.2022 ग्राम सालरिया जो खातेदार छीतर पुत्र रूपा जाति बैरवा के फोट होने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया था, को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलांत की ओर से प्रकरण में वादग्रस्त कृषि भूमि को क्रय किये जाने के संबंध में कोई रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र पेश नहीं होने से तथा अनरजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से खातेदारी अधिकारों को अंतकरण संभव नहीं होना वर्णित करते हुए कोई राहत प्रदान नहीं किये जाने के फलस्वरूप अपील अपीलांत निर्णय दिनांक 12.02.2024 से खारिज की गई।
2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12.02.2024 से अप्रसन्न होकर अपीलांत द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया कि भूमि ख.स. 289 रकबा 1.2765 है० वाके ग्राम सालरिया तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व खातेदार श्री छीतर आ० रूपा जाति चमार (बैरवा) निवासी ग्राम आमली अंकित थे जिनका देहांत सन् 1999 के पूर्व ही हो गया था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में छीतर जी के वारिसान का नाम अकन नही हुआ था तथा छीतर के एक मात्र पुत्र गंगाराम थे। छीतर जी के स्वर्गवास के साथ-साथ ही उपरोक्त वर्णित आराजी पर बतौर कानूनी रूप से खातेदार के रूप में गंगाराम काबिज हुए और गंगाराम ने काबिज होने के बाद परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपरोक्त वर्णित भूमि को दिनांक 24.12.1999 को अपीलांत को बेचान कर दिया और अपीलांत द्वारा गंगाराम को सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा करके उपरोक्त भूमि पर कब्जा संभला दिया था। गंगाराम जी के जीवनकाल से ही अपीलांत उक्त भूमि पर बतौर स्वामी अधिकार पूर्वक काबिज हो गया था तथा तभी से अनवरत रूप से गंगाराम द्वारा निष्पादित दस्तावेज के आधार पर अपीलांत उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पर

मिथु
अति.सि.अयुक्त
कम्पा

काबिज हो गया था जिसकी जानकारी गंगाराम के परिवारजनों को भी थी। गंगाराम जी ने अपने जीवनकाल में उपरोक्त वर्णित आराजी पर कभी भी अपीलांट से कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की बल्कि अपीलांट गंगाराम के जीवनकाल में अधिकार पूर्वक कृषि गतिविधियाँ उपरोक्त भूमि पर करता आ रहा है। गंगाराम के देहांत के उपरांत अपीलांट रेस्पोजेन्ट्स की जानकारी में अधिकार पूर्वक काशत करता चला आ रहा है। इस बात की जानकारी रेस्पोजेन्ट्स को दस्तावेज के निष्पादन के समय के साथ ही चली आ रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2024 एवं इंतकाल संख्या 459 दिनांक 27.05.2022 वाके ग्राम सालरिया तहसील एवं जिला बून्दी वस्तुस्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोजेन्ट्स को इस तथ्य का भलीभांति से ध्यान था कि उक्त विवादित भूमि पर बतौर स्वामी गंगाराम के जीवनकाल से ही गंगाराम जी के द्वारा निष्पादित दस्तावेज दिनांक 24.12.1999 के आधार पर अपीलांट काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है फिर भी दुर्भावनापूर्वक कब्जा न होते हुए भी रेस्पोजेन्ट्स ने अपने नाम इंतकाल खुलवाने में भारी भूल की है। रेस्पोजेन्ट्स के अपीलांट से कब्जा प्राप्त करने के अधिकार काफी समय पूर्व ही समय व्यतीत होने के साथ समाप्त हो चुके हैं फिर भी अपने नाम का लाभ उठाकर भूमियों को बेचान करने पर आमादा हो रहे हैं और इस नियती से रेस्पोजेन्ट्स ने उक्त भूमि का इंतकाल अपने नाम खुलवाया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। गंगाराम के द्वारा दिनांक 24.12.1999 को उक्त भूमि ख.स. 289 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा वाके ग्राम सालरिया को अपीलांट को बेचान कर अपीलांट से सम्पूर्ण प्रतिफल राशि 2 लाख 15 हजार 800 रु. प्राप्त कर अपीलांट को मौके पर विवादित भूमि पर कब्जा संभला दिया था तब से अपीलांट उक्त भूमि पर अनवरत रूप से रेस्पोजेन्ट्स की जानकारी में काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है ऐसी स्थिति में इंतकाल संख्या 459 निरस्त होने योग्य है। प्रथम अपील न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि दिनांक 24.12.1999 को भूमि अपीलांट को बेचान करने के बाद से आज तक उक्त भूमि के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2024 को निरस्त करते हुए इंतकाल संख्या 459 दिनांक 27.05.2022 वाके ग्राम सालरिया तहसील एवं जिला बून्दी निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट्स को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

अति.सं. 7/2024
का.सं.

हैं। प्रकरण में पक्षकारों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का उल्लेख भी उचित एवं विधिसम्मत प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी के संबंध में अपीलांट का कोई हक अधिकार सिद्ध नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.02.2024 में किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.02.2024 विधिसम्मत होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

mi 17/7/2025
(समता कुमारी तिवारी)
अति० संभागीय आयुक्त
कोटा
कोटा